भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1446

दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के लिए प्रश्न

पशुधन और डेयरी कृषि योजनाएं

1446. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने चारा और चारे की उपलब्धता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य बल गठित करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का पशुधन और डेयरी किसानों तक योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान आयोजित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को पशुधन और डेयरी किसानों के संबंध में सूक्ष्म योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पशुधन और डेयरी कृषि के संबंध में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हाँ। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश में आहार और चारे की उपलब्धता के मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों से एक कार्यबल गठित करने का अनुरोध किया है।

(ख) इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान और निकोबार राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को पशुपालन और डेयरी फ़ार्मिंग में नवीनतम प्रथाओं और तकनीकों के बारे में, डीएएचडी की विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा उनसे लाभ प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में बेहतर समझ हासिल करने में मदद करना है। डीएएचडी ने वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में 24950 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। डीएएचडी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के माध्यम से आकांक्षी जिलों में पशुधन जागृति अभियान-गहन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

(घ) चारे की कमी के मुद्दे को हल करने संबंधी कार्यबल में राज्यों के कृषि, पशुपालन और डेयरी, वन और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शामिल हैं। यह कार्यबल गौठान और अवक्रमित (डिग्रेडिड) वन भूमि में सामुदायिक चारागाह भूमि के पुनर्विकास के लिए चारे के तहत आने वाले क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास करेगा तथा भूमि और बीज उत्पादन, चारा फ़ार्मिंग तथा साइलेज/टीएमआर आदि के निर्माण हेतु निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, आईसीएआर- भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा 25 राज्यों के लिए चारा संसाधन विकास योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिसमें चारा फसलों की किस्मों, उत्पादन प्रणालियों की जानकारी, संरक्षण प्रथाएं आदि शामिल हैं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है।

(ङ) डीएएचडी, भारत सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस तथा अपने अधिकारियों के दौरे के माध्यम से पशुधन और डेयरी फ़ार्मिंग के संबंध में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

*****